

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 604वीं बैठक दिनांक 05/11/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 8919/2022 M/s Yash Logistic Private Limited, 'Yash Tower', Pathak Ward, Dist. Katni, MP - 483501 Prior Environment Clearance for Bauxite Quarry in an area of 20.151 ha. (Bauxite - 9781 Tonne per annum (Khasra No. 156, 159, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 166, 167, 168, 169/1, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 189, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 372, 249), Village - Baghrela Saani, Tehsil - Bajag, Dist. Dindori (MP) . M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.**

This is case of Bauxite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 156, 159, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 166, 167, 168, 169/1, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 189, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 372, 249), Village - Baghrela Saani, Tehsil - Bajag, Dist. Dindori (MP) 20.151 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 547वीं दिनांक 09/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाइन प्रेषित की गई है ।

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

आज दिनांक 05/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री एन.पी. मिश्रा प्रतिनिधि और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज बॉक्साइट का खनन ओपन कास्ट सेमीमेकेनाईज्ड विधि से किया जायेगा, जिसमें ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं हैं। खनन के दौरान कुल स्वीकृत रकबा 20.151 हे. में से 09.803 हे. रकबा में उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन पश्चात् 0.888 हे. क्षेत्र में बैकफिलिंग की जायेगी तथा उस पर वृक्षारोपण भी किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत रकबा 20.151 हे. नॉन फॉरेस्ट भूमि है जिसमें से 11.618 हे. निजी भूमि तथा 8.533 हे. शासकीय भूमि है। पर्यावरणीय अध्ययन के दौरान शेड्यूल-1 प्रजाति नहीं पाई गई। प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के बीच से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पगडंडी/कच्चा रोड़ है तथा आवागमन हेतु आवंटित खनन क्षेत्र के बाहर पश्चिम दिशा में रास्ता उपलब्ध है। यह पगडंडी/कच्चा रोड़ खनन क्षेत्र में आवागमन का रास्ता होगा तथा इसके दोनो ओर वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार खनन क्षेत्र में स्थित कुछ मकानों के बारे में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनका उपयोग कार्यालय आदि के रूप में किया जायेगा। आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्व एवं उत्तर दिशा में स्थित मकानों के बारे में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनसे सुरक्षित दूरी (100 मीटर) छोड़कर खनन कार्य प्रस्तावित किया गया है जिस कारण 20.151 हे. में से मात्र 09.803 हे. क्षेत्र में खनन प्रस्तावि किया गया है तथा इस खनन प्रक्रिया के दौरान ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 96 पेड़ लगे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनमें से मात्र 01 पेड़ काटा जायेगा तथा उसके एवज में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 11.618 हे. निजी भूमि है जो बेगा जनजाति की है तथा उसे परियोजना प्रस्तावक के अनुसार एग्रीमेंट कर खनन कार्य हेतु लिया गया है। चूंकि निजी भूमि जनजाति की है अतः उनके पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास हेतु क्या योजना प्रस्तावित है कि विस्तृत जानकारी प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक नहीं प्रदान कर सके। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्रस्तुत करें :-

1. आवंटित खनन क्षेत्र में 11.618 हे. जो निजी भूमि है वह कितने आदिवासियों की है उसे खसरा नंबर के हिसाब से तालिका व खसरा मेप पर (भूमि के माप) से दर्शाया जाये।
2. जिन-जिन आदिवासियों की निजी भूमि खनन कार्य हेतु उपयोग में लाई जानी है उन सभी से किये गये एग्रीमेंट की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने यह बताया था कि लगभग 15.00 एकड़ भूमि किसी एक आदिवासी ने अन्य आदिवासियों से एग्रीमेंट कर खनन हेतु प्रस्तुत की है। अतः इस एग्रीमेंट का आधार तथा यदि भूमि क़य कर एग्रीमेंट किया गया है तो उसके विधि अनुरूप दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
4. आवंटित खनन क्षेत्र में 11.618 हे. निजी भूमि जो आदिवासियों की है को खनन कार्य में उपयोग करने पर आदिवासी भूमि स्वामी को क्षतिपूर्ति (Compensation) किस नियम से कितना-कितना दिया जायेगा तथा खनन कार्य पश्चात् किस प्रकार इस निजी भूमि को कृषि कार्य हेतु पुर्नस्थापित (Restore) किया जायेगा, वित्तीय प्रस्ताव ई.एम.पी. में शामिल कर प्रस्तुत करें।

**604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 नवम्बर 2022**

5. आवंटित खनन क्षेत्र में 11.618 हे. निजी भूमि का वर्तमान कृषि उत्पाद तथा उसका मूल्य क्या है की जानकारी प्रमाणिक स्रोत से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये ।
6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 96 पेड़ लगे हैं जबकि ड्रोन वीडियो ग्राफी से पेड़ों की संख्या अधिक दिख रही है अतः इसकी पुनः एक बार पुष्टि करा ली जाये ।

**2. Case No 8934/2022 Shri Veer Vikram Singh, Bhanu Palace, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh, MP Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (25050 cum per annum) (Khasra No. 507/2), Village - Jamonya Johar, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Noida U.P.**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 507/2), Village - Jamonya Johar, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 548वीं दिनांक 10/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 05/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री वीर विक्रम सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवारोटेक इं.प्रा. लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 16/09/21 अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र नरसिंहगढ़ वन्य प्राणी अभ्यारण्य से 1.480 किलोमीटर की दूरी पर होना उल्लेखित है जबकि संबंधित नोटिफिकेशन दिनांक 27/07/18 में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (ई.एस.जेड.) की सीमा 100 मीटर से 02 किलोमीटर तक दूरी तक निर्धारित है, अतः एकल प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित खनन क्षेत्र पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा के अंदर है अथवा नहीं । अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि संबंधित वन मण्डलाधिकारी से यह स्पष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये कि आवंटित खनन क्षेत्र नरसिंहगढ़ वन्य प्राणी अभ्यारण्य की अधिसूचित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (ई.एस.जेड.) की सीमा से बाहर कितनी दूरी पर स्थित है । समिति की यह भी अनुशंसा है कि सिया द्वारा जो एकल-प्रमाणपत्र का प्रारूप दिया गया है उसमें डी. एफ.ओ. से यह स्पष्ट उल्लेख करवाया जाये कि प्रस्तावित खदान वन क्षेत्र से कितनी दूरी पर स्थित है एवं यदि खदान अधिसूचित ई.एस.जेड. के पास स्थित है तो वह ई.एस.जेड. से कितनी दूरी पर है तथा अधिसूचित ई.एस.जेड की सीमा से बाहर है ताकि प्रकरणों के निराकरण में सुविधा हो ।

**604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 नवम्बर 2022**

**3. Case No 9381/2022 M/s Shri Shakambari Ferrous Pvt. Ltd, Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil - Niwas, Dist. Mandla, MP - 481661, Prior Environment Clearance for Billets and TMT Bar at Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil - Niwas, Dist. Mandla (MP)**

This is case of Prior Environment Clearance for 49000 Tonne Per Annum capacity of Billets and TMT Bar at Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil - Niwas, Dist. Mandla (MP).

This is a rolling mill project. All non –toxic secondary metallurgical processing industries manufacturing >5000 tones/annum metal components are covered under the EIA Notification 2006 as amended 2009 and are mentioned at S.N 3(a), B. Hence these projects are required to obtain prior EC before establishment. The case was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TORs' to carry out EIA and prepare EMP for the project.

The case was presented by the PP Shri Bharat Khandelwal and their Env. Consultant Shri G.K. Mishra from M/s. Global Management & Engineering Consultants International, Jaipur. During presentation, it was observed by the committee that online uploaded Google image of approx. 8.00 to 10.00 ha area while in presentation and online uploaded project details the proposed area is 1.99 ha., which is a serious discrepancy on part of PP. similarly, the capacity is also mentioned differently in online application (In Category of the Project/Activity it is provided as 0.049 MTPA while in Common Application Form at point no. 1.4 Description of Project the capacity is mentioned as 5,00,000 TPA) which needs necessary corrections. Thus committee after deliberations asked PP to submit clarification on above and submit corrected details of the project proposal for its further consideration.

**4. Case No 9385/2022 M/s M.P.Industrial Development Corporation, Shri Ajay Kumar Jain, Excutive Engineer, 101, 1st floor, Atulya IT Part, Khandwa Road, Dist. Indore, MP - 452010, Prior Environment Clearance for Proposed Development of Tilghara Industrial Park at Village - Tilghara, Tehsil - Badnawar, Dist. Dhar, MP. Caregory-7-C, Industrial Estates/ Parks/ Complexes/ Areas, Export Processing Zones (Epzs), Special Economic Zones (Sezs), Biotech Parks, Leather Complexes. Env. Consultant:- M/s. Envisolve LLP, Indore.**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Development of Tilghara Industrial Park at Village - Tilghara, Tehsil - Badnawar, Dist. Dhar, MP. Caregory-7-C, Industrial Estates/ Parks/ Complexes/ Areas, Export Processing Zones (Epzs), Special Economic Zones (Sezs), Biotech Parks, Leather Complexes.

**604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 नवम्बर 2022**

प्रकरण आज सेक की 604वीं बैठक दिनांक 05/11/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**5. Case No 9378/2022 M/s Perfect Tar Coat Pvt. Ltd, Shri Sohail Ali Khan S/o Shri Mansoor Ali Khan, Director, 778, Napiar Town, Dist. Jabalpur, MP - 482001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (53,000 Cum per annum) (Khasra No. 98/1), Village - Dobhi, Tehsil - Narayanganj, Dist. Mandla (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 98/1), Village - Dobhi, Tehsil - Narayanganj, Dist. Mandla (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सोहेल अली खान (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 13/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऐरिया मैप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग 220 से 230 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र (कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 13/09/2022) अनुसार वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्रमांक 1249 दिनांक 17/06/22 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में कोई वन क्षेत्र नहीं है। उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशांसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 220 से 230 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इस स्थिति स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये। समिति की यह भी अनुशांसा है कि सिया द्वारा जो एकल-प्रमाणपत्र का प्रारूप दिया गया है उसमें डी.एफ.ओ. से यह स्पष्ट उल्लेख करवाया जाये कि प्रस्तावित खदान वन क्षेत्र से कितनी दूरी पर स्थित है एवं यदि खदान अधिसूचित ई.एस.जेड. के पास स्थित है तो वह ई.एस.जेड. से कितनी दूरी पर है तथा अधिसूचित ई.एस.जेड की सीमा से बाहर है ताकि प्रकरणों के निराकरण में सुविधा हो।

**604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 नवम्बर 2022**

**6. Case No 9379/2022 M/s Adiyogi Mines, Shri Pankaj Singh S/o Shri Kishan Pal Singh, Partner, 310, Plot No. 4, Top Floor, Vardhman Taru Plaza, C.U.Block, Local Shopping Centre, Pithampura, Dist. Delhi - 110034, Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.0 ha. (30612 Cum per annum) (Khasra No. 109), Village - Aindalpur, Tehsil - Kurwai, Dist. Vidisha (MP)**

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 109), Village - Aindalpur, Tehsil - Kurwai, Dist. Vidisha (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स एफएफईसीसीएम, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 918 दिनांक 18/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में लगभग 160 मीटर पर जल रोकने की संरचना है तथा पूर्व भाग से होकर एक कच्चा रास्ता निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि म.प्र. एम.एम.आर. 1996 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप 10 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है तथा संरक्षण हेतु रोड़ के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी दिशा में एक अन्य खदान खुदी हुई दिख रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह किसी के द्वारा अवैध खनन किया गया है क्योंकि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) विदिशा द्वारा जारी एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 918 दिनांक 18/04/2022 में यह सूचित किया गया है कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत होकर अनुबंधित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तावित एम-सेंड प्लॉट लीज के उत्तरी भाग में स्थापित किया जायेगा जो व्ही.एस.आई. तकनीक पर आधारित है। एम-सेंड प्लॉट से निकलने वाले दूषित जल का पुनर्उपयोग किया जायेगा जिस हेतु सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव दिया गया है तथा सेटलिंग टैंक से निकलने वाली स्लज का अपवहन सुखाकर खनन क्षेत्र में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 05/11/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन तथा एम-सेंड- 30,612 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.24 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.45 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.40 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम भौरासा के शासकीय स्कूल में पुताई और छत मरम्मत	1.40 लाख

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, करंज, चिरौल, आवला, कचनार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	600
3	ग्राम आदलपुर के स्कूल, पंचायत व आंगनवाड़ी के प्रांगण में	नीम, कदम, पीपल, करंज, बेल, अशोक एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
4.	ग्राम आदलपुर एवं भौरासा के ग्रामवासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, बेर, नीबू, महुआ, अमरुद, शहतूत एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3100
		कुल वृक्षारोपण	4800

**7. Case No 9380/2022 Shri Zafar Mohammad S/o Shri Ajar Mohammad, 502, C-Block, Rigaliya Heights, Koh-e-fiza, Dist. Bhopal, MP - 462001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.630 ha. (16815 Cum per annum) (Khasra No. 5, 6/1, 164/2), Village - Takiya, Tehsil - Shyampur, Dist. Sehore (MP)**

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 5, 6/1, 164/2), Village - Takiya, Tehsil - Shyampur, Dist. Sehore (MP) 3.630 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र पाटीदार, अधिकृति प्रतिनिधि (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोएडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

(खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3468 दिनांक 07/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर एवं पूर्व दिशा में लगभग 15 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड एवं आबादी, दक्षिण-पूर्व दिशा में 750 मीटर पर है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एम.पी. एम.एम.आर., 1996 अनुसार कच्चे रोड प्रतिबंधित दूरी 10 मीटर है तथा इस प्रकरण में 7.5 मीटर का बैरियर जोन मिलाकर दूरी 22.5 मीटर होती है। कच्चे रोड के संरक्षण हेतु लीज बाउण्ड्री में रोड की तरफ (तीन लाईन में) तथा रोड के ऊपर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में एक पेड़ स्थित है जो काटा नहीं जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिहोर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-4 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 16,815 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 18.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 06.92 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम धनोरा के ऑगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों के बैठने के लिए 8 टेबल-कुर्सी तथा बची हुई राशि से 1 वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।	60,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4366 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1400
2	परिवहन मार्ग	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400
3	तकिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद।	2516
4.	शासकीय विद्यालय तकिया, में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	50
कुल			4366

**604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 नवम्बर 2022**

**8. Case No 9384/2022 Shri Yagya Jat S/o Shri Kailash Jat, 107/1, Tripurti Nagar, Dist. Dhar, MP - 454001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (21000 Cum per annum) (Khasra No. 958 Peki), Village - Khareli, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP)**

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 958 Peki), Village - Khareli, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 05/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री यज्ञ जाट (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 261 दिनांक 17/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में एक रोड़ 90 मीटर पर स्थित है एवं उत्तर-पश्चिम दिशा में 860 मीटर की दूरी पर आबादी है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवेदित खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में रोड़ नेटवर्क दिख रहा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में किसी आवासीय या औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाना प्रस्तावित है । उपरोक्त रोड़ नेटवर्क के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक कोई समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सके अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे इस संदर्भ में वे सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) से यह विवरण प्राप्त कर कि आवेदित खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में क्या विकासत्मक गतिविधि प्रस्तावित है तदुपरांत प्रकरण पर आगे विचार किया जाये।

**9. Case No 9270/2022 Shri Abhilash Kashyap, Owner, Lakshmev Bhawa Near Little Kingdom School Ke Pass, Shanta Mandir, Near Aastha Parishar, New Ramnagar, Adhartal, Dist. Jabalpur, MP - 482004, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.290 ha. (24290 cum per annum) (Khasra No. 521, 522) Village - Toormadar, Tehsil - Kundam, Dist. Jabalpur, MP**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 521, 522) Village - Toormadar, Tehsil - Kundam, Dist. Jabalpur, (MP) 3.290 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 को प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि जबलपुर जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोड़कर अन्य गौड खनिज)

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

अनुमोदित हेतु अभी अप्राप्त है तथापि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने । सिया द्वारा उपरोक्त प्रकरण को 753वी बैठक दिनांक 26/10/22 को रिलिस्ट किया गया ।

आज दिनांक 05/11/22 को परियोजना प्रस्तावक अभिलाश कश्यप (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित जैन, कागनीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1526 दिनांक 17/5/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 147 मीटर पर पक्का रोड़ स्थित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो पेड़ बैरियर जोन में लगे हैं उन्हें नहीं काटा जायेगा तथा आवंटित खनन क्षेत्र के मध्य में लगे 01 पेड़ में से 03 पेड़ काटे जाये उसके एवज में 30 अतिरिक्त लगाये जावेगे । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि जबलपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक में परीक्षण हेतु अप्राप्त है । परियोजना ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर के पत्र क्रमांक 1525 दिनांक 17/5/22 के माध्यम से सूचित किया है कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाई जा रही है एवं नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान का विवरण दर्ज किया जावेगा । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश द्वारा एक अन्य प्रकरण में 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) निर्णय लिया है कि :-

“राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकारण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया – चूंकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक की अनुशंसा पर सिया द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिए वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किये जाना उचित होगा । पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर सिया एवं सेक को सूचित किया जाये” ।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 24,290 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.98 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.47 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
तूरमदार तालाब के किनारे वृक्षारोपण एवं सौंदर्यकरण कराया जाएगा।	1,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, रीठा, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	सेजी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलों, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2500
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
कुल			4000

### **10. Case No. - 5670/2018 Shri Maa Cimentech Pvt. Ltd, Shri Dileep Gupta, 158, 3rd Floor, Zone-II, M.P.Nagar, Bhopal MP – 462011 Prior Environment Clearance for Granite Deposit in an area of 11.0 Ha.. (33,501 ton per annum) (Khasra no. Part 63) at Vill. Barha, Teh. Gaurihar, Dist. Chhatarpur, (MP)**

This is case of Granite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra no. Part 63) at Vill. Barha, Teh. Gaurihar, Dist. Chhatarpur, (MP) 11.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Assistant Mining Officer, Distt. Chhatarpur vide letter no. 2918 dated:

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

04/12/2017 has reported that there is no more mine operating or proposed within 500 meters around the said mine.

The case was presented in SEAC 313th meeting on dated 18/04/18 by PP and their consultant wherein EIA/EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for Granite mining lease in an area of 11.00 ha., for 33,501 TPA at Khasra No. part 63 at Village –Barha Teh-Gaurihar, Distt-Chhatarpur- (M.P) subject to some conditions. प्रकरण में सिया के पत्र क्रमांक 908 दिनांक 31/5/18 के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति ग्रेनाइट-33,501 टन/वर्ष के लिए जारी की गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक ने फार्म-4 में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में ग्रेनाइट-33,501 टन/वर्ष के साथ-साथ एम-सेंड- 1,72,232 घनमीटर/वर्ष (को-प्रोडक्ट) हेतु संशोधन हेतु आवेदन किया गया है ।

आज दिनांक 05/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप कुमार गुप्ता (ऑनलाईन) एवं उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित गौर, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च प्रा.लि, नोएडा उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि खदान में खनन कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले ओवर वर्डन से एम-सेंड बनाई जाना प्रस्तावित है । वर्तमान में ..... घनमीटर ओवर वर्डन एकत्रित है तथा भविष्य में खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले ओवर वर्डन से एम-सेंड बनाई जायेगी । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्तमान में खनन के दौरान अधिक मात्रा में वेदर्ड मटेरियल निकल रहा है, अतः यदि इसका उपयोग एम-सेंड बनाकर किया जाता है तो उसके लाभकारी उपयोग हो सकेगा तथा इस प्रकार वेस्ट मटेरियल का सदुपयोग हो सकेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एम-सेंड प्लांट व्ही. एस.के. तकनीकी पर आधारित है, जिसमें वायु प्रदूषण की संभावना नगण्य है । इसी प्रकार एम-सेंड निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले दूषित जल का सेटलिंग के पश्चात् प्रक्रिया में पुनर्उपयोग किया जायेगा तथा उत्पन्न स्लज को स्लज ड्राइंग बेड में सुखाकर माइन पिट में अपवहित किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस संशोधन हेतु उनके द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र (दिनांक 08/09/22) तथा संशोधित माइन प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित (दिनांक 26/10/22) कराया गया है, जो ऑनलाईन अपलोड है । इसी प्रकार प्रस्ताव से संबंधित पुनरीक्षित पीएफआर एवं पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना (एम-सेंड को शामिल करते हुए) तैयार की गई है, जो ऑनलाईन भी अपलोड है । समिति के पूछे जाने पर परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि फार्म-4 के सरल क्रमांक-11 पूर्ण विवरण ऑनलाईन फार्म भरते समय वर्ड की लिमिटेशन होने के कारण पूर्ण रूप से दर्शित नहीं हो रहे हैं । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा नियमानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन सिया को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके विवरण उनकी वेबसाइट पर दर्शित है । समिति ने पाया कि सिया की वेबसाइट पर छःमाही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के विवरण निम्नानुसार दर्शित है :-

*“Compliance report for the period of Jan. to June 19 received on 03-08- 19. Compliance report for the period of July to Dec. 19 received on 22-01-20. Compliance report for the period of Dec. 20 received on 18-12- 20. Compliance report for the period of June 21*

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

*received on 23-06-21. Compliance report for the period of June 22 received by email on dated 28-06-22”.*

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा विगत 02 वर्षों में 600 पौधें खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में, परिवहन मार्ग पर व ग्रामीण क्षेत्र में लगाये गये हैं, जिसके फोटोग्राफ प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में परियोजना प्रस्तावक को 1288 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था जिसके एवज् में परियोजना प्रस्तावक ने 02 वर्षों में 600 पौधें खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में, परिवहन मार्ग पर व ग्रामीण क्षेत्र में लगाये गये हैं, समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि शेष 688 पौधे लगा कर उनके फोटोग्राफ एवं सी.इ.आर योजना के अंतर्गत किये गये कार्यों का अनुपालन प्रतिवेदन सहित पुनः प्रस्तुत करे तत्पश्चात उनके प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृत के संशोधन संबंधी प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

### 11. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

#### 1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, दमोह – (अन्य गौण खनिज –रेत को छोड़कर)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र०. 565 दिनांक 31/08/22 (SEAC कार्यालय में दिनांक 28/10/2022 को प्राप्त) के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट— दमोह (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एवं जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

Mineral	Other than Sand
DSR received from District Collectorate ( Mining)	Vide District Collectorate ( Mining) Office, Damoh , No. 565 dated 31.08.2022
SEAC meeting dated 05/11/22	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल –09 (पेज न०. 24–30) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है।</li> <li>जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंत में टेबिल–22 (पेज न०. 61–63) मे दे दी गई है।</li> </ul>

आज दिनांक 05/11/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला— दमोह के पत्र क्र० 565/खनिज/2022 दिनांक 31/08/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एवं प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति दमोह जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज –

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

### 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, शिवपुरी (संशोधित) – (अन्य गौण खनिज –रेत को छोड़कर)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 1433 दिनांक 21/10/22 के माध्यम से संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– शिवपुरी (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया:–

- जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–03 (पेज न0. 08–22) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नहीं दी गई है। 16 कॉलम की जानकारी पूर्ण नहीं है।
- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी भी नहीं दी गई है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि शिवपुरी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एवं रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की जावे।

### 3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – अशोकनगर (रेत खनिज)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 174/खनि/3–6/2022 दिनांक 21/10/22 एवं 179 दिनांक 01/11/22 के माध्यम से संशोधित रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। उक्त पत्र में उल्लेख है, कि टंकण त्रुटि होने के कारण संशोधन कर जिले की कमेटी के समक्ष डी.एस.आर. प्रस्तुत की गयी थी जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन पश्चात् पुनः संशोधित डी.एस.आर. सेक को ऑन लाईन भेजी गयी है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पत्र क्र0. 1956 दिनांक 28/10/22 को अशोकनगर की जिले की डी.एस.आर. अद्यतन किये जाने की जानकारी दी गयी है एवं इस संबंध में पत्र में सदस्य सचिव सिया एवं जिला कलेक्टर अशोकनगर की दूरभाष पर चर्चा भी हुयी है इसका उल्लेख है। ज्ञात हो कि अशोकनगर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) सेक की 594वीं बैठक में दिनांक 21/09/2022 के अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु सिया को प्रेषित की गयी थी।

आज दिनांक 05/11/2022 को संशोधित अशोकनगर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री अशोक सिंघारे, सहायक खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। जिले की संशोधित अशोकनगर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि:–

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के एनेक्सर –III पेज क्र०. 25 में दी तालिका के सरल क्र०. 1 के (खैरोना ग्राम) कॉलम 8 की क्षमता पूर्व में 30,000 के स्थान पर 30,084 क्यूबिक मी. पुनरिक्षित गणना कर लिखा गया है एवं सरल क्र०. 5 में कुम्हरा ग्राम के लीज एरिया की लंबाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन किया गया है। समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि तालिका में शेष अन्य प्रविष्टियां ठीक पाई गईं।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला-अशोकनगर के पत्र क्र० 174 दिनांक 21/10/22 एवं पत्र क्र० 179 दिनांक 01/11/22 के माध्यम से मिनरल पोटेन्शियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेन्शियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

#### 4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, टीकमगढ़ (संशोधित) –(अन्य गौण खनिज –रेत को छोड़कर)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र०. 4092 दिनांक 31/10/22 के माध्यम से संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट- टीकमगढ़ (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

Mineral	Sand
Earlier DSR Discussed	SEAC 591th , Meeting dated 27.08.2022.
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues )	Recommended for DSR Updation ( <b>Minor Mineral</b> )
Deliberation in the SEAC 591th , Meeting dated 27.08.2022	<p>राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)</p> <p>आज दि०. 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री एस.जेड अली, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। टीकमगढ़ जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फॉर्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारीयों वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है। टेबिल क्रमांक- (पेज क्र०. 11 से 24) की जानकारी जो माइनर मिनरल (रेत छोड़कर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।</li> <li>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फॉर्मेट के टेबिल क्रमांक-9 अनुसार कई वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है।</li> </ul>

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

	<p>चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि टीकमगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई गौण खनिज के प्रकरणों में जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।</p> <p>बैठक में उपस्थित श्री एस.जेड अली, खनिज अधिकारी, को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें।</p>
<b>Revised DSR received from District Collectorate ( Mining)</b>	Vide District Collectorate ( Mining) Office, Tikamgarh, No. 4092 dated 31.10.2022
<b>Hard Copy Soft Copy or both</b>	Hard copy & Soft copy.
<b>SEAC meeting dated 05/11/22.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक-9 (पेज क्र0. 23 से 28) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है।</li> <li>जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी ( Table) पेज क्र0. 69 से 75 में दी गई है एवं वृक्षारोपण में फोटोग्राफ्स का भी समावेश किया गया है।</li> </ul>

आज दिनांक 05/11/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री एस. जेड अली, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला— टीकमगढ़ के पत्र क्र0 4092/खनिज/2022 दिनांक 31/10/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एवं प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति टीकमगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

### जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों पर चर्चा –

निम्नानुसार उल्लेखित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज अधिकारियों द्वारा आज की बैठक के दौरान प्रस्तुत की गयी। यह प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं था किंतु संबंधित खनिज अधिकारियों/निरीक्षकों के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान की गई।

### 5. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – इंदौर (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 1994 दिनांक 02/11/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट इंदौर (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर) प्रस्तुत की गयी है। जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर) को परीक्षण करने पर पाया गया कि:—

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर 03 पेज क्र०. 19-37 के अंतर्गत जो खदानों की जानकारी दी गयी है। वह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट के अनुसार नहीं है जैसें

- केप्टिव/गैर केप्टिव खदानों संबंधी जानकारी।
- पर्यावरणीय निकासी अभिप्राप्त (हाँ/नहीं) यदि हा तो पर्यावरण निकासी अनुदत्त करने की तारीख सहित पत्र संख्या एवं दिनांक संबंधी जानकारी।
- खनन पट्टे की अवस्थिति (अक्षांश एवं देशांशतर) संबंधी जानकारी।
- खनन की विधि (खुली/भूतिगत) आदि।
- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी भी नहीं दी गयी है।

अतएव चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है, कि इंदौर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर) को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य अद्यतन में (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज) को पुनः पुनः प्रस्तुत की जायें।

### जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुशंसाओं में त्रुटि सुधार -

#### 6. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – शहडोल (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 752वीं बैठक दिनांक 15/10/2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

“राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति” (SEAC) की 594 वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 में शहडोल (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है:—

.....शहडोल की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

आज दिनांक 05/11/2022 की बैठक में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट शहडोल (रेत खनिज) में चर्चा की गयी। समिति ने परीक्षण उपरांत यह पाया कि शहडोल जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट को सेक की 598वीं बैठक दिनांक 07 अक्टूबर 2022 को सिया को अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की ओर प्रेषित की गई थी जो कि टाईपोग्राफीकल त्रुटि के कारण यह वाक्य नहीं लिख पाया गया। अतएव “शहडोल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) को अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित है ऐसा पढ़ा जावे, एवं पूर्व में प्रेषित कार्यवाही विवरण 598वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 (पृष्ठ क्र०. 51) में पूर्ववत् जारी अनुशंसा यथावत् रहेगी।

### 7. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –बैतूल (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर)

“राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति” (SEAC) की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर) जिला– बैतूल की अनुशंसा वाले पैराग्राफ में जिला बैतूल के स्थान पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट शहडोल अंकित हो गया था जिसे टंकण त्रुटि के सुधार उपरांत जिला बैतूल पढ़ा जाये एवं पूर्व में प्रेषित कार्यवाही विवरण 598वीं बैठक दि०. 07/10/2022 (पृष्ठ क्र०.-54) में जारी अनुशंसा यथावत् रहेगी।

(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

### **Annexure- 'A'**

#### **Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.  
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be  $1/4^{\text{th}}$  or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - i. Minable Potential of sand mine.
  - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
  31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।  
**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

### नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

### Annexure- 'C'

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
  15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
  16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
  17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
  18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
  19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
  20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
  21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
  22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
  23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    - o. Minable Potential of sand mine.
    - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
  27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साइड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

## 604वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained